(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा समाज कल्याण योजनाओं पर सम्मिलित रूप से किया गया कुल व्यय विकसित देशों द्वारा इस पर किए गए व्यय की तुलना में देश के सकल घरेलू उत्पाद का बहुत ही छोटा प्रतिशत हिस्सा है;

(ख) देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए समाज कल्याण योजनाओं पर वार्षिक

व्यय को बढ़ाने हेतु प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में समाज कल्याण योजनाओं के वित्तपोषण के लिए तलाशी जा रही नवोन्मेषी

वित्तपोषण योजनाओं/मॉडलों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्‍हा)**

(क) वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान के अनुसार केंद्र और राज्‍य सरकारों का सामाजिक सेवाओं पर सम्‍मिलित व्‍यय स.घ.उ. का 6.9 प्रतिशत है। उपर्युक्‍त सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, खेल, कला और संस्‍कृति; चिकित्‍सा और सार्वजनिक स्‍वास्‍थ्‍य; परिवार कल्‍याण; जलापूर्ति तथा स्‍वच्‍छता; आवास; शहरी विकास; अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्‍य पिछड़े समुदायों के लोगों का कल्‍याण; श्रम तथा श्रमिक कल्‍याण; सामाजिक सुरक्षा एवं कल्‍याण; पोषण; प्राकृतिक आपदाओं की स्‍थिति में राहत कार्य; आदि शामिल हैं। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) की वर्ष 2014 में प्रकाशित तथ्‍य पुस्‍तिका के अनुसार 2013 में ओईसीडी देशों का सार्वजनिक सामाजिक व्‍यय स.घ.उ. का 21.9 प्रतिशत था। ओईसीडी द्वारा प्रकाशित तथ्‍य पुस्‍तिका के अनुसार सामाजिक व्‍यय में नकद लाभ, वस्‍तुओं एवं सेवाओं को प्रत्‍यक्ष रूप में उपलब्‍ध कराना तथा सामाजिक प्रयोजनों से दिए गए कर छूट शामिल हैं।

(ख) भारत सरकार विभिन्‍न समाज कल्‍याण योजनाएं चला रही है। चलाई जा रहीं समाज कल्‍याण योजनाओं के अतिरिक्‍त, सरकार द्वारा ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में स्‍वास्‍थ्‍य, शिक्षा, स्‍वच्‍छता, रोजगार, आवास, सड़क निमार्ण आदि जैसे महत्‍वपूर्ण क्षेत्रों में कुछ नई नवोन्‍मेषी समाज कल्‍याण योजनाएं/कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें से कुछ योजनाएं निम्‍नलिखित हैं: स्‍वच्‍छ भारत मिशन (ग्रामीण), जिसका उद्देश्‍य वर्ष 2019 तक ''खुले में शौच से शत-प्रतिशत मुक्‍त भारत'' के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करना है; दीनदयाल उपाध्‍याय ग्रामीण कौशल योजना, जो ग्रामीण युवकों के स्‍थापन से जुड़ी कौशल विकास योजना है; शहरी गरीब लोगों को कौशल प्रदान करने के लिए राष्‍ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम); कौशल आधारित प्रशिक्षण हेतु राष्‍ट्रीय कौशल विकास मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना; शहरी गरीब लोगों की आवासीय आवश्‍यकता हेतु सभी (शहरी) के लिए आवास मिशन/प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई); भाषा और गणितीय विकास हेतु ‘पढ़े भारत बढ़े भारत’; तथा एक वर्ष के भीतर प्राथमिक स्‍कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय बनाने के लिए स्‍वच्‍छ विद्यालय संबंधी पहल करना, आदि। इसके अलावा, आधार से जुड़ी प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) वित्‍तीय समावेशन और सामाजिक योजनाओं के लाभों को सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा करने में भरपूर योगदान कर रही है। सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर तीन महत्‍वपूर्ण योजनाएं अर्थात अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी चलाई गई है।

(ग) प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) और समाज कल्‍याण योजनाओं के लाभों को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने से समाज कल्‍याण योजनाओं के लाभों को उपलब्‍ध कराने के मार्ग की कमियों को दूर करने में मदद मिलती है जिसके परिणामस्‍वरूप समाज कल्‍याण योजनाओं पर नए सिरे से बल देने से उल्‍लेखनीय वित्‍तीय बचत भी होती है। नई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं अर्थात अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इस जनधन प्‍लेटफार्म का प्रयोग करती और बैंकों/बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी स्‍थापति करती है। जिससे कि गरीबों को दुर्घटना अथवा वृद्धावस्‍था में दरिद्रता की स्‍थिति में सहारा तथा सहायता सुनिश्‍चित की जा सके।

\*\*\*\*\*